https://shikshabodh.in/

SHIKSHA BODH
(The Journal of Education and Humanities)
A quarterly, peer-reviewed/refereed journal
ISSN: 3139-5880 IMPACT FACTOR: 6.50
VOLUME-1| ISSUE-4 | October-December, 2026

ग्रामीण उच्च शिक्षा एवं सरकारी सहयोग: वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और समावेशी विकास की संभावनाएँ

डॉ. शिवेश प्रसाद राय
असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञान विभाग (राजनीति)
अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुबेछपरा, बलिया
ईमेल – shiveshrai73@gmail-com
Mobile No- 9450725750

सारांश

भारत गांवों का देश है। यहां जनसंख्या का 65 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं। विज्ञान और तकनीकी के विकास ने ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतरों को कम कर दिया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, भौतिक संरचना और संस्थागत विकास में मूलभूत अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें व्यापक सुधार एवं विकास की आवश्यकता है। ग्रामीण उच्च शिक्षा मानव विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति और बौद्धिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विकास क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, युवाओं की क्षमता का उपयोग करने तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में ग्रामीण उच्च शिक्षा की स्थिति, सरकारी सहयोग, वित्तीय संसाधनों, संस्थागत गुणवत्ता, डिजिटल विभाजन और रोजगारपरक शिक्षा का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, सरकारी नीतियों और उपलब्ध सांख्यिकीय सूचनाओं पर आधारित है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)2023.24 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत तथा महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 प्रतिशत था। ये आँकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विस्तार को दर्शाते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान(PM & USHA), डिजिटल शिक्षण तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की संभावनाओं का मूल्यांकन करते हुए लेख तर्क प्रस्तुत करता है कि ग्रामीण उच्च शिक्षा में केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य शिक्षक, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, समयबद्ध वित्तीय सहायता, स्थानीय अर्थव्यवस्था से संबद्ध पाठ्यक्रम और जवाबदेह प्रशासन भी आवश्यक हैं। निष्कर्षतः, देश और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजना, आवश्यकता-आधारित सरकारी निवेश और संस्थागत सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्य शब्दः ग्रामीण उच्च शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी सहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामाजिक समावेशन, डिजिटल विभाजन, रोजगारपरक शिक्षा।

प्रस्तावना:

शिक्षा के बिना मानव विकास की कल्पना असंभव है। शिक्षा ही मानव को पशु से मानव बनाती है। शिक्षा मानव जीवन में ज्ञान, विवेक, कौशल और सामाजिक चेतना के विकास का प्रमुख माध्यम है। उच्च शिक्षा की भूमिका विद्यालयी शिक्षा से आगे बढ़कर नेतृत्व, अनुसंधान, नवाचार, व्यावसायिक दक्षता, लोकतांत्रिक सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन तक विस्तृत होती है। ग्रामीण समाज के संदर्भ में उच्च शिक्षा का महत्त्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यह कृषि, स्थानीय उद्यमिता, सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक न्याय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में योगदान दे सकती है।

भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के बावजूद उसकी उपलब्धता और गुणवत्ता सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों की भौगोलिक उपलब्धता, सुगम पहुंच, महाविद्यालयों में भौतिक संरचना, मानव संसाधन की उपलब्धता, शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों और आर्थिक सहायता की स्थिति विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार उच्च शिक्षा की समस्या केवल नामांकन तक सीमित नहीं हैय इसमें शिक्षा की निरंतरता, गुणवत्ता, पाठ्यक्रम पूर्णता और उपाधि के बाद उपलब्ध अवसर भी सम्मिलित हैं। भावी नागरिकों में आवश्यक जीवन कौशल, आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण का विकास अपेक्षित है।

ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक परिवेश उच्च शिक्षा के प्रश्न को विशेष महत्त्व प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ कृषि आधारित रोजगार, छोटे व्यापार, कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र और अन्य राज्यों में रोजगार के लिए प्रवासन आजीविका के महत्त्वपूर्ण आयाम हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए निकटवर्ती महाविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख माध्यम हो सकते हैं। किंतु किसी संस्थान की भौगोलिक उपलब्धता अपने आप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी नहीं है। विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण, उचित मार्गदर्शन, आधुनिक अध्ययन सामग्री और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के वैकल्पिक संस्थाओं जैसे दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालयीय शिक्षा के विकास एवं पहुंच पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, किंतु गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं की जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा को बहुविषयक, लचीला, कौशल-आधारित, अनुसंधानपरक और समावेशी बनाने पर बल दिया है। नीति में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय एवं राज्यकीय योजनाओं के साथ जोड़ना आवश्यक है। बिना ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में निवेश और विकास के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक एवं वैचारिक परिप्रेक्ष्य:

भारत की शिक्षा परंपरा में ज्ञान, नैतिकता, तर्क, दर्शन और व्यावहारिक कौशल की विविध धाराएँ रही हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जयिनी, एन्नेरियम, सलोत्गी, कश्मीर और वल्लभी जैसे ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र ज्ञान-विकास की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी प्राचीन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा लगभग नगण्य रही है। गुरुकुल, बौद्ध मठ एवं बिहार, मंदिर, टोल, पाठशालाएं, मस्जिद से जुड़े मकतब एवं मदरसे शिक्षा के अर्धसंस्थागत केन्द्र रहें हैं तथापि, इन संस्थानों की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को आधुनिक अर्थों में सार्वभौमिक ग्रामीण उच्च शिक्षा की उपलब्धता के समान नहीं माना जा सकता। अतीत की शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के सामाजिक आधार, संस्थागत स्वरूप तथा अवसरों में पर्याप्त अंतर रहा है। आज हमारी उच्च शिक्षा से अपेक्षाएं एवं उद्देश्य प्राचीन शिक्षा की अपेक्षा एवं उद्देश्यों से बिल्कुल अलग हैं, जिनकी पूर्ति केवल आधुनिक उच्च शिक्षा के संस्थान ही कर सकते हैं।

औपनिवेशिक काल में, चाल्स वुड के आज्ञापत्र के आलोक में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में स्थापित मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बम्बई विश्वविद्यालय से आधुनिक विश्वविद्यालयों और औपचारिक उच्च शिक्षा संस्थानों का शुरुआत एवं विस्तार हुआ, लेकिन शिक्षा तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की पहुँच सामाजिक और भौगोलिक रूप से असमान बनी रही। इस संदर्भ में हंटर आयोग (1881) ने अपने विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया जिसके बाद जिला शिक्षा परिषदों ने ग्रामीण शिक्षा की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कदम बढ़ाया। फिर भी औपनिवेशिक काल के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रगति उल्लेखनीय नहीं है। हर्टोग समिति (1929) ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को एक विकट समस्या के रूप में रेखांकित किया। महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम (1937) ने हस्तकला आधारित शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के साथ आत्मसात करने की ओर ध्यान खींचा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व संबंधी आदर्शों ने शिक्षा के विस्तार को व्यापक सामाजिक उद्देश्य प्रदान किया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या ने उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया, लेकिन संस्थानों की गुणवत्ता और संसाधनों का समान वितरण और अवस्थापना आज भी महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए

ग्रामीण विश्वविद्यालय की संकल्पना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग/राधाकृष्णन आयोग (1948-49) ने सुझाया। डॉ. के. एल. श्रीमाली की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण उच्च शिक्षा आयोग (1955) ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। आयोग ने अपने रिपोर्ट में ग्रामीण उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, संकाय प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में वृद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सन 1956 में गांधी ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु के गांधीग्राम, डिंडीगुल में स्थापित हुआ, जिसके पाठ्यक्रम में ग्रामीण विकास, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय समस्याओं को स्थान दिया गया। कोठारी आयोग (1964-66) और राष्ट्रीय नीति 1986 ने अपने प्रतिवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास पर बल दिया जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सूत्रपात हुआ। 1991 में मध्यप्रदेश के चित्रकूट जिले में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को केंद्रित ग्रामीण विकास को समर्पित है।

विश्व बैंक एवं भारत सरकार की संयुक्त पहल राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP)ने भारत में कृषि एवं ग्रामीण उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन 25,000 से बढ़कर 54,000 से अधिक हुआ है तथा समय पर डिग्री पूर्ण करने की दर 96.1 प्रतिशत तक पहुँच गई है। महिला भागीदारी बढ़कर 45.2 प्रतिशत और स्नातकों की रोजगार दर 67 प्रतिशत हुई है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों ने 120 से अधिक कृषि स्टार्टअप स्थापित किए तथा 600 से अधिक पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण किया गया, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI), रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और प्रिसिजन फार्मिंग जैसे विषय शामिल हैं। हालाँकि, ग्रामीण एवं शहरी उच्च शिक्षा के बीच आधारभूत संरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी की असमानता अभी भी चुनौती बनी हुई है। अतः NEP -2020 के अनुरूप संस्थागत स्वायत्तता, डिजिटल सुविधाओं के विस्तार तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

वर्तमान समय में ग्रामीण उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण या आधुनिक व्यावसायिक कौशल का विकास नहीं है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन, स्थानीय ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहकारी कार्य संस्कृति और आजीवन सीखने की क्षमता का विकास भी सम्मिलित होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक विज्ञान, मानविकी, लोकविद्या, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा एवं प्रबंधन को महत्व दिया जाना चाहिए। कृषि, वानिकी, कुटीर उद्योग, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, भाषा, लोकविद्या, आप्रवासन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ और उच्च शिक्षा:

अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय, दैनिक मजदूरी, सेवा क्षेत्र और प्रवासन से प्राप्त आय पर निर्भर हैं। ऐसी परिस्थितियों में उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को व्यापक रोजगार बाजार तक पहुँच प्रदान कर सकती है और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता की संभावनाएँ भी विकसित कर सकती है। स्थानीय लोकविद्या, स्थानीय ज्ञान कौशल को व्यापक मानव अध्ययन के केंद्र में लाकर विश्वव्यापी लोकविद्याशास्त्र के साथ समन्वित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय साक्षरता, कृषि उत्पादों के विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्यमिता, सहकारी संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन से संबंधित कौशल विकसित किए जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अध्ययन के आधार पर तैयार किए जाएँ। केवल किसी पाठ्यक्रम को रोजगारपरक घोषित कर देना उसके वास्तविक रोजगार परिणामों का प्रमाण नहीं है। 'एक जिला एक उत्पाद' प्रोजेक्ट के आलोक में ऐसे उत्पादन प्रक्रिया को ग्रामीण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम भी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों, दिव्यांग विद्यार्थियों और परिवार में पहली बार उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को अलग-अलग प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन व्यय, अध्ययन सामग्री, पाठ्यक्रम चयन, डिजिटल उपकरण, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और रोजगार की आवश्यकता उनकी शैक्षणिक निरंतरता को प्रभावित कर सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सुझाव एवं परामर्श हेतु विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया जा सकता है। महिला विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रावास, गर्ल्स कॉमन रूम, स्वच्छता सुविधाएँ, परामर्श और आर्थिक सहायता विशेष महत्त्व रखती हैं। इसलिए उच्च शिक्षा की

समानता का मूल्यांकन केवल नामांकन से नहीं, बल्कि नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम पूर्णता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आगे की शिक्षा और रोजगार संबंधी अवसरों से भी किया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति: राष्ट्रीय आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण:

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन, शिक्षक, आधारभूत संरचना और अन्य शैक्षणिक संकेतकों के संबंध में भारत सरकार का प्रमुख आधिकारिक स्रोत है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी । AISHE 2022-23 और 2023द्24 की रिपोर्टों के अनुसार, भारत का उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात 2023द्24 में 30 प्रतिशत तक पहुँच गया। महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 प्रतिशत था। इसी वर्ष अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 27.8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का 22.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्तमान में 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 60 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीणध्अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात मात्र 7.51 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 23.79 प्रतिशत है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जिनका सकल नामांकन अनुपात केवल 5.67 प्रतिशत है। ये आँकड़े ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुँच, शैक्षिक अवसरों तथा लैंगिक समानता में विद्यमान गहरी असमानताओं को रेखांकित करते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)2023-24 और नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 545 विश्वविद्यालयध्विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान संचालित हैं। इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों में से 245 सरकारी और 300 निजी संस्थान हैं। आधिकारिक ट्रैकिंग के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर के किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को बंद नहीं किया गया है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़कर 27.9 लाख हो गया है, जो पहले 20.1 लाख था। यह ग्रामीण विश्वविद्यालयों में छात्रों के नामांकन में 38.3ः की वृद्धि को दर्शाता है। बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज (B.R.S) जैसे विशेष पाठ्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी और वार्षिक नामांकन में निरंतर रुचि देखी गई है।

ये आँकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी का संकेत देते हैं। महिला नामांकन अनुपात में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रत्येक राज्य या जिले में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी समान स्तर पर पहुँच गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात किसी विशेष ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक अंतर समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय आँकड़े व्यापक प्रगति का संकेत देते हैं, जबकि क्षेत्रीय आँकड़े संसाधनों, संस्थागत गुणवत्ता और वास्तविक शैक्षणिक अवसरों में अंतर स्पष्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का प्रमाणिक मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-स्तरीय नामांकन, महाविद्यालयों की संख्या, विषयवार शिक्षक उपलब्धता, प्रयोगशालाओं, छात्रवृत्ति और पाठ्यक्रम पूर्णता संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण करना होगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विस्तार को स्वीकार करते हुए भी क्षेत्रीय असमानताओं की जाँच आवश्यक है। किसी क्षेत्र विशेष में अधिक महाविद्यालय होना अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करता कि वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, शोध सुविधाएँ और रोजगारपरक अवसर भी पर्याप्त हैं।

ग्रामीण उच्च शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ:

ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास में आधारभूत संरचना की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर, इंटरनेट, उपयुक्त कक्षाएँ और अध्ययन-अनुकूल वातावरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक सुविधाओं का अभाव विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान को सीमित कर सकता है, जबकि सामाजिक विज्ञान और मानविकी में शोध-पत्रिकाओं, ई-पुस्तकों तथा विश्वसनीय डिजिटल संसाधनों तक पहुँच आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न है। स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों के बीच अंतर, विषय-विशेषज्ञों की कमी तथा अनुसंधान के सीमित अवसर शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका समाधान नियमित नियुक्तियों, शिक्षक विकास कार्यक्रमों, शोध सहयोग और विश्वविद्यालयों के साथ संस्थागत साझेदारी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

तेजी से हो रहे तकनीकी विकास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन की समस्या बरकरार है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल पुस्तकालयों ने अध्ययन सामग्री तक पहुँच की संभावनाएँ बढ़ाई हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास उपयुक्त उपकरण, स्थिर इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता उपलब्ध नहीं होती। इसलिए ग्रामीण महाविद्यालयों में साझा डिजिटल अध्ययन केंद्र, परिसर में इंटरनेट,

ई-पुस्तकालय और ऑफलाइन अध्ययन सामग्री की व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

आर्थिक बाधाओं की चुनौती को कमतर नहीं आंका जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त परिवहन, आवास, भोजन, पुस्तकें और डिजिटल संसाधनों का खर्च भी महत्त्वपूर्ण होता है। छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान, आवेदन सहायता और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए परामर्श व्यवस्था शिक्षा की निरंतरता में योगदान दे सकती है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की अत्यधिक शुल्क ग्रामीण परिवेश के मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए एक तरह से असंभव होता जा रहा है, इसे सरकार के स्तर पर नियंत्रित और सब्सिडाइज करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण परिवेश के अनुरूप पाठ्यक्रम और रोजगार के बीच संबंध के संतुलन और जुड़ाव की समस्या महत्वपूर्ण बाधा की तरह है। यदि पाठ्यक्रम स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं और बदलते श्रम बाजार से पर्याप्त रूप से संबद्ध नहीं हैं, तो स्नातकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। डिजिटल कौशल, संचार, डेटा विश्लेषण, उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता उपयोगी हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नागरिक उत्तरदायित्व का विकास भी आवश्यक है।

सरकारी सहयोग, योजनाएं और नीतिगत पहल:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन, अनुसंधान, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाविद्यालयों की संस्थागत क्षमता का विस्तार, पाठ्यक्रम के स्थानीय मांग की पहचान, भौतिक और मानवीय संसाधन की उपलब्धता, स्थानीय संस्कृति और भाषा को शिक्षा से जोड़ना, वित्तीय संसाधन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकास पर ध्यान देना होगा।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान(PM - USHA): यह राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने, आधारभूत संरचना विकसित करने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय आवश्यकताओं को सम्मिलित करने, स्थानीय भाषाओं को महत्व प्रदान करने तथा रोजगारपरक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए महत्त्वपूर्ण योजना है। इसकी दिशा-निर्देशों में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए बेहतर संस्थानों तक पहुँच, डिजिटल शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और संस्थागत गुणवत्ता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों के लिए इस प्रकार की योजनाओं की उपयोगिता उनकी पात्रता, स्वीकृत परियोजनाओं और वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इसलिए योजना का नाममात्र उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं हैय संस्थानों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार करने, संसाधनों का पारदर्शी उपयोग करने और परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थिति एक विकट समस्या है, उच्च शिक्षा के छात्र किसी न किसी व्यवसाय, सेवा, उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसे में उनकी उपस्थिति की समस्या के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2026द्27 के केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा विभाग के लिए ₹55,727.22 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो 2025-26 के बजट अनुमान से 11.28 प्रतिशत अधिक है। यह केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग का आवंटन हैय इसे ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों को सीधे प्राप्त होने वाली राशि नहीं मानना चाहिए।

वित्तीय आवंटन का मूल्यांकन करते समय केवल वृद्धि प्रतिशत देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई, कितने संस्थानों को सहायता मिली, संसाधनों का वितरण किन मानदंडों पर हुआ और उससे शैक्षणिक परिणामों में कितना सुधार आया। पूर्वांचल के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता, नियमित शिक्षक नियुक्तियाँ और प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के रखरखाव पर व्यय विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजना, गांव की बेटी योजना, SHREYAS, उत्तर प्रदेश दशमोत्तर (Post - Matric) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (मुफ्त कोचिंग) ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए सार्थक पहल हैं।

ग्रामीण संस्थान अक्सर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कम डिजिटल कनेक्टिविटी, गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर और योग्य शिक्षकों की कमी से जूझते हैं। वित्तीय तंगी, सामाजिक असमानता और ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन स्थानीय शैक्षणिक

विकास को प्रभावित करता है। भारत में प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास 5 एकीकृत यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है, जो उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को एक साथ जोड़ेंगे। एडटेक और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म (जैसे स्थानीय भाषाओं में सिखाने वाले एआई टूल्स) ग्रामीण छात्रों तक व्यक्तिगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचा रहे हैं। पारंपरिक डिग्री को स्थानीय ग्रामीण जरूरतों से जोड़ने के लिए औपचारिक संस्थानों (जैसे गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान) और गैर-औपचारिक कौशल केंद्रों (जैसे बेयरफुट कॉलेज) का मिश्रण तैयार किया जा रहा है। नई शैक्षणिक नीतियां केवल नौकरी पाने पर नहीं, बल्कि नेतृत्व और सामाजिक क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं ताकि युवा अपने ही क्षेत्रों का विकास कर सकें।

राष्ट्रीय नीति और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यापक स्तर पर शिक्षा की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों को स्थानीय समस्याओं के अनुरूप कार्ययोजना की आवश्यकता है। इन दोनों स्तरों के बीच समन्वय स्थापित करना ग्रामीण उच्च शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य है। क्षेत्रीय स्तर पर इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और पर्याप्त शैक्षणिक संसाधन मिलें। इसी प्रकार डिजिटल शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अवसर प्रदान करती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर उपकरणों, इंटरनेट और तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इसका लाभ समान रूप से नहीं पहुँच सकता। वित्तीय दृष्टि से भी समान आवंटन और समान अवसर में अंतर है। कमजोर आधारभूत संरचना वाले महाविद्यालयों को अपेक्षाकृत अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता का महत्त्व उन विद्यार्थियों की तुलना में अधिक हो सकता है, जिन्हें परिवार से पर्याप्त संसाधन प्राप्त हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करना होगा। जिला-स्तरीय आँकड़ों, संस्थानवार आवश्यकताओं और विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित नीति अधिक प्रभावी हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावहारिक सुझाव:

सबसे पहले प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। इसमें महाविद्यालयों की उपलब्धता, विषयवार शिक्षक, विद्यार्थियों का नामांकन, छात्रवृत्ति, डिजिटल सुविधाएँ और पाठ्यक्रम पूर्णता जैसे संकेतक शामिल हों। इस आधार पर जिला ग्रामीण उच्च शिक्षा विकास योजना बनायी जा सकती है। महाविद्यालयो को स्थानीय अर्थ व्यवस्था से जोड़न के लिए कृषि खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्यमिता, सहकारी संस्थाओं और डिजिटल सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं पर लघु शोध, इंटर्नशिप और परियोजना-आधारित अध्ययन के अवसर दिए जा सकते हैं। आसपास के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच साझा डिजिटल पुस्तकालय, प्रयोगशाला सुविधाएँ, शिक्षक कार्यशालाएँ और शोध सहयोग विकसित किया जाना चाहिए। इससे सीमित संसाधनों वाले संस्थानो को विशेषज्ञता और अध्ययन सामाग्री तक बेहतर पहुंच मिल सकती है, प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति, कैरियर परामर्श, डिजिटल आवेदन और शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना उपयोगी होगा। महिला विद्यार्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और प्रथम पीढ़ी के उच्च शिक्षा प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आवंटित सरकारी अनुदान के उपयोग का मूल्यांकन केवल व्यय की गई राशि के आधार पर न करके शैक्षणिक परिणामोंध्उपलब्धियों से भी जोड़ा जाना चाहिए। सकल नामांकन, ड्रॉपआउट, उपस्थिति, पाठ्यक्रम पूर्णता, शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों के उपयोग, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विद्यार्थियों के रोजगार संबंधी परिणामों (प्लेसमेंट), परामर्श एवं सुझाव प्रदाय प्रकोष्ठ का नियमित मूल्यांकन संस्थागत जवाबदेही बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में ग्रामीण उच्च शिक्षा का विकास सामाजिक न्याय, आर्थिक गतिशीलता और क्षेत्रीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी सकारात्मक संकेत देती है, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य शिक्षकों, आधारभूत संरचना, डिजिटल पहुँच और आर्थिक सहायता की स्थिति का अलग से मूल्यांकन आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और PM-USHA । जैसी योजनाएँ ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास के लिए नीतिगत अवसर प्रदान करती हैं। फिर भी उनकी सफलता

पर्याप्त संसाधनों, प्रभावी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता और पारदर्शी मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। पूर्वांचल में जिला-विशिष्ट योजना, आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता, स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा पाठ्यक्रम और महाविद्यालयों के बीच सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का अध्ययन को अनुभवजनित शोध का विषय बनाकर प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधिक विश्वसनीय समीक्षा की जा सकती है। इसलिए प्रस्तुत आलेख विश्लेषण को क्षेत्र-केंद्रित नीतिगत अध्ययन के रूप में समझना चाहिए, न कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आधारित निष्कर्ष। भविष्य में सर्वेक्षण आधारित तुलनात्मक अध्ययन इस विषय को अधिक ठोस अनुभवजन्य आधार प्रदान कर सकता है। अंततः, ग्रामीण उच्च शिक्षा पर सरकारी व्यय को मानव संसाधन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समानता और क्षेत्रीय विकास में दीर्घकालीन निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की वास्तविक प्रगति तभी सुनिश्चित होगी, जब ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रत्येक योग्य विद्यार्थी आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने जीवन, समाज और क्षेत्र के विकास में कर सके।

संदर्भ सूची:

- Ministry of Education, Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
- Ministry of Education, Government of India. (2026a, July 8). *Union Ministry for Education releases reports of the All India Survey on Higher Education (AISHE): 2022–23 & 2023–24*. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282525
- Ministry of Education, Government of India. (2026b, February 1). *Union Education Minister lauds historic budget 2026–27, calling it a Yuva Shakti driven budget—a budget for human capital for Viksit Bharat*. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221734
- Ministry of Education, Government of India. (n.d.). *Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyaan (PM-USHA)*. Retrieved October 29, 2026, from https://pmusha.education.gov.in/
- Baloj, S. A. (2021). Status of higher education in rural areas of India. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 9(8), e497–e504.
- Google. (2026, October 30). *British period rural higher education in India*. Google Search. https://www.google.com/search?q=british+period+rural+higher+education+in+india
- DDA247. (n.d.). *Which of the following commissions under the chairmanship of Dr. K. L. Shrimali submitted its report in 1955 regarding problems in higher education in India?* https://dda247.com/question-answer/which-of-the-following-commissions-under-the-chairmanship-of-dr-k-l-shrimali-submitted-its-report-in-1955-regarding-problems-in-higher-education-i/q.v1.c2c88e21-8b64-4f44-b58a-bc824c3b2a38-en
- The Hindu. (2025). *Proposed HECI could lead to closure of institutions in rural areas, fuel privatisation: Parliament panel*. The Hindu. https://www.thehindu.com/education/proposed-heci-could-lead-to-closure-of-institutions-in-rural-areas-fuel-privatisation-parliament-panel/article69180270.ece
- Google. (n.d.). *World Bank report on Indian rural higher education: Latest*. Google Search. Retrieved October 30, 2026, from

https://www.google.com/search?q=world+bank+report+on+indian+rural+higher+education+latest

- Arnhold, N., Dey, S., Goyal, S., Larsen, K., & Tognatta, N. (2022). *Realizing the promise of the National Education Policy: From good to great in Indian tertiary education*. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080503142332315/pdf/P1747790711faf048085a70993d530a04de.pdf
- World Bank. (2026, April 3). *From classrooms to careers: How India made agricultural degrees job-ready*. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/results/2026/04/03/how-india-made-agricultural-degrees-job-ready
- World Bank. (2025, September 15). *Cultivating change in agricultural education: The rise of tech-driven learning in India's agriculture universities*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/09/08/cultivating-change-in-agricultural-education-the-rise-of-tech-driven-learning-in-india-s-agriculture-universities